चिल्ड्रन प्रेस सर्विस बुलेटिन

वर्ष - २ | अंक - ४ | पृष्ठ संख्या - १२ | प्रकाशनार्थ नई दिल्ली, मई-अगस्त २००७

प्रधान संपादक
हसरत अर्जुमन्द

संपादक
आशेन्द्र सिंह

सलाहकार मंडल
के. कन्नन
गजेन्द्र नौटियाल
उमेश कुमार
बिभास
शैलेष

संपर्क पता
चिल्ड्रन प्रेस सर्विस बुलेटिन
c/o ग्रासरूट्स मीडिया इनीशियेटिव
प्रथम तल, रेल आरक्षण बिल्डिंग
५० ए, स्ट्रीट १७, ज़ाकिर नगर, ओखला
नई दिल्ली - ११० ०२५
दूरभाषः ०११-२६८८३४४६, २६८३५४५२,
०८८६८४६६४०१, ०६६६६०४२८८८
ई-मेलः grassrootsmediainitiative@gmail.com
वेबसाइटः www.childrenpress.org

ए.पी. ग्राफ़िक्स, टी-१६ ओखला फ़ेस-२
नई दिल्ली - ११० ०२० द्वारा मुद्रित

सीमित वितरण हेतु

आपका स्वागत है...

हमारे प्रयासों की एक और कड़ी में आपका स्वागत है । अपने कुछ शुभचिंतकों की सलाह पर अमल करते हुए हम ''चिल्ड्रन प्रेस सर्विस'' बुलेटिन की व्यापकता को बढ़ाने के लिए उसे बेवसाइट पर ले आए हैं । अब सी.पी.एस. बुलेटिन के सभी नए-पुराने अंक बेवसाइट पर देखे और पढ़े जा सकेंगे, साथ ही पाठक अपनी प्रतिक्रियाएं भी आसानी से दर्ज़ करा सकेंगे । हमारे इस प्रयास को साकार करने में जिन लोगों का सहयोग मिला उनका अति आभार ।

कुछ माह पहले राजस्थान स्थित उरमूल सेतु संस्थान के सहयोग से बच्चों को आंगनबाड़ी केंद्र की स्थिति पर लेखन के लिए ई सी सी डी मीडिया फेलोशिप का आयोजन किया गया । इसके अलग-अलग चरणों में बच्चों को मैदानी भ्रमण करा आंगनबाड़ी के व्यावहारिक पक्ष से अवगत कराया गया । साथ ही आंगनबाड़ी पर लेखन की सैद्धांतिक तकनीकें बताई गईं। फ़ोटोग्राफ़ी और कॉमिक्स जैसे माध्यमों के प्रयोग का प्रशिक्षण भी उन्हें दिया गया । इसके परिणाम में बच्चों ने जो रचनाएं लिखीं उनसे उनके सपनों की आंगनबाड़ी की झलक मिलती है । फिलहाल सी.पी.एस. बुलेटिन के इस अंक में हमने फैलोशिप के अंतर्गत प्राप्त कुछ रचनाओं को प्रकाशित किया है । शेष रचनाओं को हम जल्द ही पुस्तकाकार में संजोकर लाएंगे ।

इन रचनाओं के माध्यम से आइए हम और आप भी बाल रचनाकारों की दृष्टि से आंगनबाड़ी केंद्रों को देखें ।

❑ *संपादक*

Plan
Be a part of it

विकलांगों को आंगनबाड़ी केंद्र पर सुविधाएं नहीं

❑ *विमला लेघा*

''म्हाने तो उण रो लाभ मिले कोनी । म्हाने तो आंगनबाड़ी री बाई बतावै जको ही साचो लागे है ।'' ये कहना है हाथ से अपाहिज सोनू की मां का । सच भी यही है, जागरूकता व अशिक्षा के अभाव में ग्रामीणों के लिए वही सच होता है जिसकी सूचना जितनी और जिस रूप में उन तक पहुंचती है । फिर सरकार द्वारा चाहे जो भी कार्यक्रम या योजनाएं चलाई जा रही हों ।

बीकानेर जिला मुख्यालय से लगभग ७५ किमी और लूनकरनसर तहसील से क़रीब ३६ किमी की दूरी पर स्थित है लखावर गांव । सोनू इसी गांव में रहता है । गांव में एक आंगनबाड़ी केंद्र संचालित है । इसमें एक कार्यकर्ता और एक सहायिका है। इस केंद्र पर बच्चों को अन्य सुविधाओं के अतिरिक्त शाला-पूर्व शिक्षा भी मुहैया कराई जाती है । इसमें विकलांग बच्चे भी शामिल हैं जो हाथ, पांव, आंख व कान से विकलांग बच्चे हैं । विकलांग बच्चों को आत्मनिर्भर बनाने और समाज की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए यद्यपि सरकार कई तरह की योजनाएं चला रही है, लेकिन इस योजना का पूरा लाभ ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे विकलांग बच्चों को नहीं मिल रहा । आंगनबाड़ी केंद्रों पर इनके लिए विशेष सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं ।

सरकार द्वारा जो सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रहीं हैं उनकी पूरी जानकारी इन्हें नहीं है । इस संबंध में आंगनबाड़ी केंद्र की सहयोगिनी कुंती ने बताया, ''आंगनबाड़ी केंद्र पर विकलांग बच्चों के लिए कोई अलग से सुविधा उपलब्ध नहीं है । अगर सरकार कोई सुविधा देती भी है तो वह हम तक नहीं पहुंच पाती ।''

उन्होंने बताया कि ''हम कार्यकर्ता तो विकलांग बच्चों के साथ प्यार से पेश आते हैं और दूसरे बच्चों के समान ही उन्हें पोषाहार शिक्षा तथा अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं, लेकिन विकलांग बच्चों के लिए हम अलग से सुविधाएं कहां से लाएं?'' इस प्रकार लखावर आंगनबाड़ी केंद्र में विकलांगों को अलग से सुविधाएं न मिल पाने से इन्हें पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा । इसके लिए इनके मां-बाप का अशिक्षित होना और जागरूकता का अभाव भी ज़िम्मेदार है ।

● **चिप्रेस**

नोटः इस सामग्री का उपयोग होने पर प्रकाशित कतरन कृपया अवश्य भेजें ।

* *विमला* बीकानेर जिले के लखाबर गांव की रहने वाली है ।
* इस आलेख को इंटरनेट से डाउनलोड करने हेतु क्लिक करें : www.childrenpress.org/

शाला पूर्व शिक्षा का इंतजार है इन ४० बच्चों को

❑ *हरचंद लेघा*

तहसील मुख्यालय से लगभग ४० किमी की दूरी पर स्थित गांव अजीतमाना के आंगनबाड़ी केंद्र में शाला पूर्व शिक्षा आज भी सपना बनी हुई है । ३-६ वर्ष के ४० बच्चे आंगनबाड़ी केंद्र पर शाला पूर्व शिक्षा देने के लिए नामांकित हैं, इनमें २० लड़के व २० लड़कियां हैं । जब से इन बच्चों के लिए गर्म पोषाहार व्यवस्था लागू की गई है तब से इनको इस पोषाहार के साथ-साथ शाला पूर्व शिक्षा से भी हाथ धोना पड़ा है ।

यहां की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता अन्नी देवी हैं । सहायिका व सहयोगी विमला देवी व जेता देवी हैं । ये तीनों आठवीं तक पढ़ी हुई हैं । ३-६ वर्ष के बच्चों के लिए आंगनबाड़ी हर रोज़ खोलना प्रस्तावित है, लेकिन अजीतमाना का आंगनबाड़ी केंद्र कभी-कभार ही खुलता है । जब कभी केंद्र खुलता है तो कुछ बच्चे शाला पूर्व शिक्षा लेने के लिए आ जाते हैं । इन बच्चों के पास ना स्लेट है और न ही कापी, पेंसिल हैं । आंगनबाड़ी पर बच्चों को कुछ बताने के लिए कोई चार्ट वग़ैरह भी नहीं हैं ।

बच्चों को बैठने के लिए दरी-पट्टी भी केंद्र पर उपलब्ध नहीं है । यदि बच्चे आते भी हैं तो समय से पहले ही घर चले जाते हैं । स्कूल जाने से पहले अभिभावक बच्चों को आंगनबाड़ी भेजकर स्कूल के नियम-क़ायदे सिखाना चाहते हैं । स्कूल में किस तरह से बैठना चाहिए, किस तरह से व्यवहार करना चाहिए तथा कुछ हाथ से लिखने का तरीक़ा आंगनबाड़ी केंद्रों पर बताया जाना होता है, लेकिन अजीतमाना के बच्चों को यह अब औपचारिक स्कूल में जाकर ही सीखना पड़ेगा ।

● **चिप्रेस**

नोटः इस सामग्री का उपयोग होने पर प्रकाशित कतरन कृपया अवश्य भेजें ।

* *हरचंद लेघा* लुनकरनसर तहसील के अजीतमाना गांव के रहने वाले हैं ।
* इस आलेख को इंटरनेट से डाउनलोड करने हेतु क्लिक करें : www.childrenpress.org/

खारी आंगनबाड़ी केंद्र खिलौने पर चढ़ी धूल

❑ *पप्पू बाला*

बीकानेर जिला मुख्यालय से ७५ और लुनकरनसर तहसील से क़रीब ३० किलोमीटर की दूरी पर स्थित है ग्राम खारी । अधिक जनसंख्या होने के कारण सरकार ने इस गांव में दो आंगनबाड़ी केंद्र खोले हैं । ये दोनों केंद्र नियमित रूप से नहीं खुलते हैं और ना ही यहां पर सही तरीक़े से पोषाहार का वितरण किया जाता है । फलस्वरूप गांव के कई बच्चों को देखकर ही पता चलता है कि वे कुपोषण के शिकार हैं । इन आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों के साथ-साथ किशोरियों और गर्भवती व धात्री महिलाओं को भी पोषाहार नहीं मिलता ।

इसके अतिरिक्त आंगनबाड़ी केंद्र के जो भी दायित्व हैं उनका निर्वहन नहीं किया जाता । दोनों आंगनबाड़ी केंद्रों के नियमित न खुलने से इसमें धूल का जमावड़ा रहता है और साफ़-सफ़ाई भी नहीं होती ।

आंगनबाड़ी केंद्र में अन्य सामग्री के साथ-साथ बच्चों के लिए खिलौने रखे हैं, लेकिन इन पर धूल की परतें जमीं हैं । इन खिलौनों को बच्चों को खेलने के लिए नहीं दिया जाता । गांव में कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक आंगनबाड़ी केंद्र देखा ही नहीं है ।

मैंने जब आंगनबाड़ी केंद्र क्रमांक एक की कार्यकर्ता से खिलौने के बारे में जानकारी लेनी चाही तो उन्होंने बताया कि सारे खिलौने टूट गए हैं, लेकिन सच यह है कि आंगनबाड़ी केंद्र नियमित न खुलने से खिलौनों की पहुंच बच्चों तक हो ही नहीं पाती ।

● **चिप्रेस**

नोटः इस सामग्री का उपयोग होने पर प्रकाशित कतरन कृपया अवश्य भेजें ।

* *पप्पू बाला* बीकानेर जिले की लुनकरनसर तहसील के खारी गांव की रहने वाली है ।
* इस आलेख को इंटरनेट से डाउनलोड करने हेतु क्लिक करें : www.childrenpress.org/

समस्याओं से घिरी आंगनबाड़ी

❑ *हबीब*

जोधपुर ज़िले के फलोदी तहसील मुख्यालय से लगभग ५० किमी की दूरी पर स्थित गांव नूरे की भुर्ज में शिक्षा का स्तर बहुत ही पिछड़ा हुआ है । गांव में स्थित आंगनबाड़ी केंद्र भी बच्चों को शाला पूर्व शिक्षा उपलब्ध नहीं करा पा रहा है । आंगनबाड़ी में पर्याप्त कर्मचारियों का अभाव लंबे समय से है ।

स्थानीय आंगनबाड़ी की सहायिका हलीमा के अनुसार गत १० माह से ज़्यादा समय हो गया आंगनबाड़ी में कार्यकर्ता, साथिन और सहयोगिनी के पद रिक्त हैं, साथ ही आंगनबाड़ी के पास अपना भवन भी नहीं है । फलस्वरूप टीकाकरण जैसी गतिविधियां नियमित नहीं हो पातीं । हलीमा ने बताया कि आंगनबाड़ी केंद्र को सही समय पर पोषाहार भी नहीं मिलता जिसके चलते बच्चों को पोषाहार का वितरण नहीं हो पाता । इन सभी समस्याओं के अतिरिक्त एक समस्या और भी महत्वपूर्ण है, और वह है पोषाहार रखने के लिए उचित स्थान का ना होना ।

कर्मचारियों के अभाव में ज़्यादातर काम हलीमा को ही करना पड़ता है । केंद्र में बच्चों को पढ़ाने के लिए चार्ट आदि भी नहीं हैं । आंगनबाड़ी की हालत सुधारने में ग्रामीण भी सहयोग नहीं करते । आंगनबाड़ी सहायिका के अनुसार गांव के लोगों में अभी भी अंधविश्वास व्याप्त है जिसके चलते गांव में लोग टीकाकरण व गर्भवती स्त्रियों के विभिन्न परीक्षणों में रुचि नहीं लेते ।

हलीमा बताती हैं कि ग्रामीणों का सहयोग न मिलने और कर्मचारियों के अभाव में केंद्र का और केंद्र से संबंधित अधिकांश मैदानी काम उन्हें अकेले ही करना पड़ता है । यदि केंद्र में पर्याप्त कर्मचारी हों तो आंगनबाड़ी की सभी गतिविधियों का लाभ बच्चों को मिल सके ।

इसके अतिरिक्त स्थानीय जनता और सरकार के सहयोग से आंगनबाड़ी का अपना भवन बन जाए तो कई समस्याओं से निजात मिल सकती है ।

● **चिप्रेस**

नोटः इस सामग्री का उपयोग होने पर प्रकाशित कतरन कृपया अवश्य भेजें ।

* *हबीब* फलोदी तहसील के नूरे की भुर्ज गांव के रहने वाले हैं ।
* इस आलेख को इंटरनेट से डाउनलोड करने हेतु क्लिक करें : www.childrenpress.org/

पंजीयन होने पर भी जननी को लाभ नहीं

❑ *कमलेश कुमार*

संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देकर मातृत्व व शिशु मृत्यु दर में कमी लाने के उद्देश्य से राजस्थान में भी जननी सुरक्षा योजना का संचालन किया जा रहा है । इस योजना के तहत गर्भवती महिलाओं का पंजीयन कर उन्हें स्वास्थ्य संबंधी देखभाल सहित अन्य लाभ भी दिए जाते हैं ।

राजस्थान में भी यह योजना चलाई जा रही है, लेकिन इसका लाभ पात्रों को नहीं मिल पा रहा । बीकानेर जिले के लूणकरनसर तहसील से ३० किलोमीटर दूर धोरों की तलहटी में बसा है बीझरवाली गांव । भागीरथ राम का परिवार इसी गांव में रहता है । यह परिवार आर्थिक दृष्टि से काफी कमज़ोर है । भागीरथ राम की पुत्रवधू जसोदा का नाम आंगनबाड़ी सहयोगिनी द्वारा गर्भधारण करने के पश्चात जननी सुरक्षा योजना के तहत पंजीकृत किया गया । साथ ही उसे यह भी आश्वासन दिया गया कि योजना के अंतर्गत मिलने वाले सभी लाभ उसे मुहैया कराए जाएंगे ।

जसोदा की सास श्रीमती धनी के अनुसार जसोदा का नाम जननी सुरक्षा योजना के तहत दर्ज होने के बावजूद उसे योजना का कोई लाभ नहीं मिला । जसोदा को ना तो टीका लगाए गए और ना ही उसे आयरन की गोलियां मिलीं । इसके अतिरिक्त उसे आंगनबाड़ी केंद्र से पोषाहार भी नहीं मिला । श्रीमती धनी के अनुसार जसोदा के प्रसव का समय नज़दीक आने पर वे आंगनबाड़ी की सहयोगिनी के पास मदद के लिए गईं, लेकिन उन्हें कोई मदद नहीं मिली । तब गांव की दाई हीरा को बुलाना पड़ा । इस बीच जसोदा की तबियत बिगड़ रही थी । तबियत को बिगड़ता देख शहर से ए.एन.एम. को लेकर आए । ए.एन.एम. ने जसोदा के चार इंजेक्शन लगाए और बदले में चार सौ रुपए ले लिए । जसोदा का प्रसव गांव की दाई हीरा द्वारा करवाया गया ।

जसोदा ने एक बच्ची को जन्म दिया जो अब लगभग दो माह की है, लेकिन उसे भी अभी तक कोई टीका नहीं लगाया गया। जसोदा के ससुर भागीरथ राम का कहना है, ''पहले ए.एन.एम. बहन जी थीं तो कुछ टीकाकरण हो जाता था, लेकिन जब से वो गईं हैं गांव में कोई टीकाकरण नहीं हुआ।'' वे आगे कहते हैं ''इसके लिए कहीं न कहीं से हम भी दोषी हैं, हम अपने अधिकारों के प्रति ना ही जागरूक हैं और ना ही उनको पाने के लिए कोई पहल करते हैं ।''

बाक्सः रोला में टीकाकरण की समस्या

जोधपुर की फलौदी तहसील के अंतर्गत एक गांव आता है रोला । इस गांव की आबादी लगभग २५०० है । गांव के आंगनबाड़ी केंद्र की कार्यकर्ता हमीदा हैं । दिसंबर २००५ से संचालित इस केंद्र के बारे में हमीदा ने बताया ''यहां विभिन्न आयु वर्ग के बच्चों, किशोरियां और महिलाओं को सभी सुविधाएं दी जाती हैं । बच्चों को शाला पूर्व शिक्षा भी दी जाती है, लेकिन स्कूल के अभाव में वे बच्चे आगे की शिक्षा से वंचित रह जाते हैं । गांव की अधिकांश आबादी मुस्लिम समुदाय की है, अतः ये लोग अपने बच्चों को हिंदी न पढ़ाकर उर्दू पढ़ाना चाहते हैं । इसके लिए एक मदरसा भी बनवाया है ।

एक ग्रामीण अब्दुल के अनुसार गांव में ए.एन.एम. के न होने से टीकाकरण नहीं हो पाता है । टीकाकरण के लिए गांव से ३५ किमी दूर नाचना कस्बे में जाना पड़ता है । इसके अलावा बच्चों के खेलने की सुविधा आंगनबाड़ी केंद्र या गांव में नहीं है ।

● **चिप्रेस**

नोटः इस सामग्री का उपयोग होने पर प्रकाशित कतरन कृपया अवश्य भेजें ।

* *कमलेश* जोधपुर जिले की फलोदी तहसील के बाप गांव का रहने वाला है और किशोरों की संस्था दूसरा दशक के जुड़ा हुआ है ।

* इस आलेख को इंटरनेट से डाउनलोड करने हेतु क्लिक करें : www.childrenpress.org/

आंगनबाड़ी केंद्र के प्रति बदलता नज़रिया

❑ *प्रकाश मेघवाल*

महिला स्वास्थ्य को लेकर आज विश्व समुदाय चिंतित है । वहीं दूसरी ओर राजस्थान में महिला स्वास्थ्य को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है । इसके पीछे कई प्रमुख कारण हैं । इनमें सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का लचर होना, लोगों में स्वास्थ्य अधिकारों के प्रति जानकारी व चेतना का अभाव प्रमुख हैं ।

ये कारण स्वास्थ्य संबंधी मामलों में अंधविश्वास व रूढ़ियों को भी बढ़ावा देते हैं । ये तो तस्वीर का एक पहलू है । दूसरी तरफ़ स्थानीय स्तर पर चलाए जा रहे प्रयासों के फलस्वरूप कुछ हद तक महिलाओं में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता आई है।

गर्भावस्था के दौरान महिला की समुचित जांच न होने से प्रसव के समय जच्चा व बच्चा दोनों को ही ख़तरा रहता है । ग्रामीण स्तर पर इस समस्या से निजात पाने के लिए आंगनबाड़ी केंद्रों की उपस्थिति महत्वपूर्ण है, लेकिन सभी आंगनबाड़ियां अपनी भूमिका का निर्वहन उचित रूप से नहीं कर रहीं हैं । अतः इसका लाभ कुछ ख़ास या गिने-चुने केंद्रों के अंतर्गत आने वाली महिलाओं को ही मिल रहा है ।

कुछ ग्रामीणों से बात करने पर पता चला कि लोग अपने घर की महिलाओं का स्वास्थ्य परीक्षण करवाने से कतराते हैं, उनकी मान्यता है कि ऐसा करवाने से हमारे देवी-देवता नाराज़ हो जाएंगे ।

जोधपुर ज़िले की फ़लोदी तहसील के अंतर्गत आने वाले जाम्बा गांव के निवासी भोजाराम इस संदर्भ में कहते हैं, ''आज से लगभग दो तीन साल पहले तक क़रीब ७० फ़ीसदी लोग अपनी महिलाओं के स्वास्थ्य की जांच नहीं करवाते थे । गत वर्ष इस लापरवाही के चलते गांव की तीन महिलाओं की मृत्यु हो गई, तब से लोगों का नज़रिया बदला है और अब वे स्वास्थ्य सेवाओं की ओर अग्रसर होने लगे हैं ।'' ग्रामीणों का नज़रिया बदलने के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ने स्थानीय नागरिकों व चिकित्सकों के सहयोग से अभियान चलाया और लोगों को समझाइश दी । अब गांव की आंगनबाड़ी पर महिला स्वास्थ्य को लेकर महिलाओं की नियमित बैठक भी होती है ।

जोधपुर जिले के अंतर्गत आने वाली बाप पंचायत समिति लगभग ४० गांवों में महिला स्वास्थ्य जांच के लिए सक्रिय है । जाम्बा आंगनबाड़ी क्रमांक १ की कार्यकर्ता का कहना है, ''गत सात माह में मैंने लगभग २० महिलाओं की स्वास्थ्य जांच कर सुरक्षित प्रसव कराया है, फलस्वरूप आंगनबाड़ी के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ा है । आंगनबाड़ी केंद्र टीकाकरण में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं फिर चाहे गर्भवती स्त्री को लगने वाले टीके हों या शिशु को लगने वाले टीके ।'' ग्रामीण भोजाराम के अनुसार पहले यह संभव नहीं हो पाता था कि वे अस्पताल जाकर अपने बच्चों को नियमित टीकाकरण करवाएं, लेकिन जब से आंगनबाड़ी केंद्र पर यह सुविधा उपलब्ध हो गई है तब से लोगों के लिए टीके लगवाना सुलभ हो गया है ।

ग्रामीण महिला श्रीमती शांती देवी का कहना है, ''ये टीके हमारे बच्चों को टिटनेस, पोलियो, टी.बी. व खसरा जैसी बीमारियों से बचाते हैं । धीरे-धीरे ग्रामीणों का विश्वास टीकाकरण और आंगनबाड़ी केंद्रों पर बढ़ता जा रहा है और झाड़-फूंक तथा अन्य रूढ़ियों के पैर कमज़ोर पड़ते जा रहे हैं ।

● **चिप्रेस**

नोटः इस सामग्री का उपयोग होने पर प्रकाशित कतरन कृपया अवश्य भेजें ।

* *प्रकाश मेघवाल* जोधपुर जिले के जाम्बा गांव के रहने वाले हैं ।
* इस आलेख को इंटरनेट से डाउनलोड करने हेतु क्लिक करें : www.childrenpress.org/

अव्यवस्थाओं के शिकार आंगनबाड़ी केंद्र

❑ *जगदीश सोनी*

सरकार द्वारा आइ.सी.डी.एस. कार्यक्रम के तहत आंगनबाड़ी केंद्रों का संचालन किया जा रहा है । राज्य के अधिकांश आंगनबाड़ी केंद्रों के पास अपना भवन न होने से वे कई तरह की अव्यवस्थाओं से जूझ रहे हैं । बीकानेर जिले की लूनकरनसर तहसील के अंतर्गत आता है ग्राम कालू । लगभग १५ हज़ार की आबादी वाले इस गांव के लिए ६ आंगनबाड़ी केंद्र स्वीकृत हैं । इसमें से केवल ३ आंगनबाड़ी केंद्र ही अपने भवन में चल रहे हैं, शेष तीन केंद्र निजी अथवा सार्वजनिक इमारतों में संचालित किए जा रहे हैं । तहसील मुख्यालय से लगभग २० किमी की दूरी पर स्थित कालू गांव का आंगनबाड़ी केंद्र क्रमांक १ पुलिस चौकी के पास बने आंगनबाड़ी भवन में, केंद्र क्रमांक २ वार्ड नंबर १६ की रा.प्रा.वि. में, केंद क्रमांक ३ स्वामी मोहल्ले की सारस्वत धर्मशाला में संचालित है ।

आंगनबाड़ी केंद्र क्रमांक ४ रा. प्रा. वि. 'कन्या' और क्रमांक ५ मोगामेड़ी स्थित सार्वजनिक भवन में संचालित है । जबकि आंगनबाड़ी केंद्र क्रमांक ६ रा.प्रा.वि. (छात्र) में चलाया जाता है । जिन आंगनबाड़ी केंद्रों के पास अपने भवन नहीं हैं उनकी हालत अच्छी नही है । इतनी अधिक आबादी वाले इस बड़े गांव में आंगनबाड़ी केंद्रों के पास अपना भवन न होने से पोषाहार रखने, बच्चों को बिठाने व पोषाहार बनाने में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है । जो केंद्र सार्वजनिक भवनों में संचालित किए जा रहे हैं वहां आंगनबाड़ी केंद्र द्वारा संचालित विभिन्न गतिविधियों के लिए पर्याप्त स्थान न होने से कार्यकर्ता व लाभार्थियों को असुविधा होती है ।

क्षेत्र के दलित व पिछड़ा वर्ग परिवारों के लोग आंगनबाड़ी केंद्रों द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं से वंचित हैं । फलस्वरूप उनके बच्चे कुपोषण के शिकार हो रहे हैं । स्थानीय नागरिकों व पंचायत समिति द्वारा आंगनबाड़ी केंद्रों की नियमित निगरानी न होने से भी केंद्रों में अव्यवस्थाएं व्याप्त है । ग्रामीणों का कहना है अगर आंगनबाड़ी केंद्रों में व्याप्त असुविधाओं और अनियमितताओं की शिकायत पंच और सरपंच से करते हैं तो वे यह कहकर पीछा छुड़ा लेते हैं कि आंगनबाड़ी तो लुगाईयों के हवाले है, उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं ?

कालू ग्राम पंचायत में कई छोटे और बड़े ग्राम आते हैं, रेतीले टीलों के बीच बसे इन गांवों के लोगों को आंगनबाड़ी केंद्र द्वारा पोषाहार, शालापूर्व शिक्षा, स्वास्थ्य परीक्षण, टीकाकरण व दवाईयों के वितरण जैसी सुविधाओं की महती आवश्यकता है। इन सुविधाओं की पहुंच व्यापक रूप से ग्रामीणों तक ना होने के पीछे जातिगत भेदभाव का रवैया और स्थानीय राजनीति भी प्रमुख कारण हैं ।

● **चिप्रेस**

नोटः इस सामग्री का उपयोग होने पर प्रकाशित कतरन कृपया अवश्य भेजें ।

* *जगदीश सोनी* बीकानेर जिले के कालू गांव के रहने वाले हैं ।

* इस आलेख को इंटरनेट से डाउनलोड करने हेतु क्लिक करें : www.childrenpress.org/

आंगनबाड़ी केंद्र की सुविधाओं से महरूम ग्रामीण

❑ *सोनू सियाग* व *भंवरी*

बीकानेर जिला मुख्यालय से १०५ व छत्तरगढ़ तहसील मुख्यालय से लगभग २१ किमी की दूरी पर बसा है महादेववाली गांव। इस गांव की कुल जनसंख्या लगभग ४ हज़ार है । इस गांव में दो आंगनबाड़ी केंद्र हैं । इसमें से एक आंगनबाड़ी केंद्र तो नियमित रूप से खुलता है, लेकिन दूसरा केंद्र यदा-कदा ही खुला मिलता है । गांव के आंगनबाड़ी केंद्र पर दवाईयां तो आती हैं, पर उनका वितरण हितग्राहियों को नहीं किया जाता । ग्रामीणों का कहना है आंगनबाड़ी केंद्र पर जो दवाईयां निःशुल्क वितरण के लिए आती हैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता उनको यह कहकर बेचती है कि दवाईयां मैं अपने पैसे से ख़रीद कर लाई हूं। आंगनबाड़ी केंद्र पर आने वाले बच्चे अगर बीमार होते हैं या उन्हें कोई तकलीफ़ होती है तो कार्यकर्ता उन्हें घर भेज देती है। इसके अतिरिक्त आंगनबाड़ी केंद्र पर गर्भवती महिलाओं को आयरन की गोलियां नहीं मिलतीं । आंगनबाड़ी केंद्र पर नियमित टीकाकरण की व्यवस्था भी नहीं है । फलस्वरूप ०-५ साल तक के बच्चों व गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण भी नहीं हो पाता । नियमानुसार आंगनबाड़ी केंद्र पर स्वास्थ्य दिवस का आयोजन होना चाहिए जो कि नहीं होता ।

ग्रामीण स्वास्थ्य दिवस के दौरान मिलने वाली सेवाओं से महरूम रहते हैं । बच्चों का नियमित स्वास्थ्य परीक्षण और वज़न लेने जैसी गतिविधियां भी नहीं होती । ग्रामीणों का कहना है कि स्वास्थ्य सेवाएं तो दूर की बात है आंगनबाड़ी केंद्र पर कर्मचारियों का भी अभाव है । एक ग्रामीण बृजलाल के अनुसार गांव के विकलांग बच्चों को आंगनबाड़ी की किसी भी सुविधा का लाभ नहीं मिलता, फलस्वरूप उनके लिए विकलांगता अभिशाप साबित हो रही है । ये बच्चे कुपोषण का शिकार भी हैं ।

प्राप्त जानकारी के अनुसार दोनों आंगनबाड़ी केंद्रों पर लगभग ४० बच्चों के नाम दर्ज़ हैं जो आंगनबाड़ी केंद्र पर आते हैं तथा ऐसे २५ बच्चों के नाम दर्ज़ हैं जिन्हें घर पर पोषाहार पहुंचाया जाता है । जबकि गांव वालों का कहना है कि यह नाम केवल रजिस्टर में ही दर्ज हैं । ना तो आंगनबाड़ी केंद्र पर आने वाले बच्चों को सही मात्रा में पोषाहार मिलता है और ना ही बच्चों को घर पर पोषाहार पहुंचाया जाता है । आंगनबाड़ी केंद्रों पर आने वाला पोषाहार कार्यकर्ता, सहयोगिनी और आशा सहयोगिनी घर पर ले जाती हैं ।

आंगनबाड़ी केंद्र पर किशोरियों के लिए कुछ सुविधाओं का प्रावधान है । गांव वालों का कहना है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता किशोरियों को कोई भी सुविधा नहीं देती तथा कहती हैं कि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है । कार्यकर्ता खानापूर्ति के लिए कभी पोषाहार का वितरण करती भी हैं तो बिना पकाया पोषाहार दे देती है । इसके अतिरिक्त अन्य जो भी लाभ दिए जाते हैं वह अपने पहचान वाले या व्यवहारी परिवारों के बच्चों को ही दिया जाता है ।

● **चिप्रेस**

नोटः इस सामग्री का उपयोग होने पर प्रकाशित कतरन कृपया अवश्य भेजें ।

* *सोनू सियाग* और *भंवरी* छतरगढ़ तहसील के महादेववाली गांव की रहने वाली हैं

* इस आलेख को इंटरनेट से डाउनलोड करने हेतु क्लिक करें : www.childrenpress.org/

पोषाहार के साथ खेल भी ज़रूरी

❑ *जेठाराम*

कहा जाता है कि एक स्वस्थ्य तन में ही एक स्वस्थ्य मन निवास करता है । स्वस्थ्य तन और मन के लिए ज़रूरी है बच्चों को पोषाहार के साथ-साथ खेलकूद के भी अवसर उपलब्ध कराए जाएं । आज के स्वस्थ्य बच्चे ही कल के ज़िम्मेदार नागरिक बनेंगे । बच्चों को पोषाहार, स्वास्थ्य व खेलकूद संबंधी सुविधाएं प्रदान करने और उन्हें शालापूर्व शिक्षा से जोड़ने के उद्देश्य से सरकार द्वारा आंगनबाड़ी केंद्र चलाए जा रहे हैं ।

जोधपुर ज़िले की फलौदी तहसील के अंतर्गत आती है ग्राम पंचायत बाप । इसी ग्राम पंचायत का एक गांव है कानासर । फलौदी तहसील मुख्यालय से इस गांव की दूरी लगभग ५६ किमी है । गांव की आबादी लगभग १२०० है । आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और ग्रामीणों से मिली जानकारी के अनुसार आंगनबाड़ी केंद्र में बच्चों का नामांकन तो पर्याप्त है, लेकिन उपस्थिति कम रहती है । इसके अतिरिक्त आंगनबाड़ी केंद्र पर साफ़-सफ़ाई की उचित व्यवस्था नहीं रहती । बच्चों को दूषित पानी पीना पड़ता है । फलस्वरूप उन्हें संक्रमित बीमारियां होने का ख़तरा रहता है । साथ ही पोषाहार बनाने और खिलाने वाले बर्तनों की सफ़ाई अच्छी तरह नहीं की जाती । इसके पीछे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का तर्क है कि केंद्र में बर्तनों का अभाव है। बच्चों के लिए पोषाहार और स्वच्छता के साथ-साथ खेलकूद संबंधी गतिविधियां भी ज़रूरी हैं । खेल के लिए ज़रूरी है कि खेल का मैदान सुरक्षित जगह पर हो और सभी की पहुंच में हो । खेल के मैदान में हरी घास और आसपास हरे-भरे वृक्ष हों । साथ ही पीने के पानी की उचित व्यवस्था हो ।

बच्चों को खेल खिलाने वाला व्यक्ति विश्वसनीय तथा समझदार होना चाहिए । बच्चों को ऐसे खेल खिलावे जो रोचक हों व सुरक्षित । खेल संबंधी गतिविधियों में संलग्न रहने से बच्चों में स्वास्थ्य प्रतिस्पर्धा की भावना का विकास होता है और उनमें आगे बढ़ने का हौसला आता है । खेल बच्चों के अंदर एकता और समानता का भाव भी लाते हैं । साथ ही शारीरिक विकास के साथ-साथ मानसिक विकास में सहायता करते हैं । यदि हम पूरे दिन में कुछ निर्धारित समय खेल संबंधी गतिविधियों को दें तो हमारी स्मरण शक्ति भी अच्छी होती है । आंगनबाड़ी केंद्र एक ऐसा स्थान है जहां पर बिना किसी भेदभाव के लड़का और लड़कियों को खेल के समान अवसर उपलब्ध कराए जा सकते हैं ।

ग्रामीण स्तर पर खेल के मैदान विकसित करने में गांववालों के साथ-साथ स्थानीय जनप्रतिनिधियों की भूमिका अहम होती है। इनके सहयोग से खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाना चाहिए ।

● **चिप्रेस**

नोटः इस सामग्री का उपयोग होने पर प्रकाशित कतरन कृपया अवश्य भेजें ।

* *जेठाराम* जोधपुर जिले की फलोदी तहसील के कानासर गांव का रहने वाला है ।
* इस आलेख को इंटरनेट से डाउनलोड करने हेतु क्लिक करें : www.childrenpress.org/

दबाव के साये में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता

❑ *विमला लेधा*

हमारे समाज में महिलाओं को प्रतिनिधित्व के अवसर तो मिलने लगे हैं, लेकिन निर्णय संबंधी अधिकार आज भी उनके पास नहीं हैं । फिर चाहे बात महिला सरपंच की हो अथवा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की ।

बीकानेर जिले के अंतर्गत एक गांव आता है लखावर । जिला मुख्यालय से लगभग ७५ किमी की दूरी पर स्थित इस गांव में एक आंगनबाड़ी केंद्र है । इस आंगनबाड़ी केंद्र की कार्यकर्ता आशा तथा सहायिका को प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करते हुए काम करना पड़ता है । इस संबंध में जब मैंनें लखावर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से बात की तो उन्होंने बताया कि हम आज भी अपनी मर्जी से काम नहीं कर सकते । किसी भी निर्णय में घर के पुरुषों की सहमति होना ज़रूरी है । आंगनबाड़ी से संबंधित कोई भी व्यवस्थागत निर्णय लेना हो तो उसमें हमें ससुर, पति अथवा देवर की सहमति लेनी पड़ती है, साथ ही इसे सामाजिक स्वीकृति भी मिलनी चाहिए अन्यथा लोग कहते हैं कि तुम्हारे घर में तो औरतों की चलती है । जब हम पोषाहार वितरण करते हैं अथवा टीकाकरण, स्वास्थ्य दिवस या अन्य किसी कार्यक्रम का आयोजन करते हैं तो ग्रामीण कई तरह के आरोप-प्रत्यारोप लगाते हैं । अशिक्षा और जागरूकता के अंधेरे में रह रहे ग्रामीणों की नज़रों में स्त्री का स्थान चूल्हा-चौका तक ही है ।

आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ने बताया ''उधर मानदेय के लिए हमें अधिकारियों के कार्यालय के चक्कर काटने पड़ते हैं । हमारे मानदेय का उपयोग कैसे होगा इसका निर्धारण घर के पुरुष करते हैं । आंगनबाड़ी में किस तरह का काम किया जाए इसका निर्धारण गांव के सरपंच या अन्य वरिष्ठ लोग करते हैं । हम पर हमेशा दबाव बना रहता है । हमारे काम में कई तरह की ग़लतियां निकाली जाती हैं । साथ ही उचित प्रशिक्षण भी नहीं दिया जाता । समाज व ग्रामीणों की हमसे अपेक्षाएं तो बहुत हैं, लेकिन इन अपेक्षाओं पर खरा उतरने के लिए हमें पर्याप्त अवसर उपलब्ध नहीं कराए जाते । दबाव के साये में रहकर हम जितना कर सकते हैं उतना करते हैं ।''

यह स्थिति सिर्फ़ इस आंगनबाड़ी केंद्र की महिला कार्यकर्ताओं की ही नहीं है बल्कि कमोवेश इन्ही परेशानियों का सामना ज़्यादातर आंगनबाड़ी महिला कार्यकर्ता कर रही हैं ।

● **चिप्रेस**

नोटः इस सामग्री का उपयोग होने पर प्रकाशित कतरन कृपया अवश्य भेजें।

* *विमला लेधा* बीकानेर जिले के लखावर गांव की रहने वाली है ।

* इस आलेख को इंटरनेट से डाउनलोड करने हेतु क्लिक करें : www.childrenpress.org/